भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1727

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन

1727. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश भर में नगरपालिका सेवाओं का डिजिटलीकरण करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त मिशन में सामुदायिक केन्द्रों की ऑनलाइन बुकिंग और संपत्तियों के पंजीकरण आदि जैसे नए मॉड्यूल होंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन वर्ष 2021 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के सभी शहरों और कस्बों में शहरी शासन और सेवा प्रदत्त के प्रति नागरिक-केन्द्रित और पारिस्थितिकी- प्रेरित दृष्टिकोण को संस्थागत बनाना था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त कार्यक्रम के लिए 2024-25 के बजट में आबंटित निधियों को अभी तक मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) में डिजिटल नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा उपयोग योग्य साझा

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और प्रबंधन की परिकल्पना की गई है, जिससे ईज ऑफ लिवींग और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ाने में योगदान मिलेगा। इस मिशन के प्रायौगिक कार्यान्वयन की शुरूआत फरवरी, 2021 में की गई थी।

इस योजना में [(अर्बन पलेटफोरम फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गर्वनेंस (उपयोग)] नामक नागरिक केंद्रित शहरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निरूपण की परिकल्पना की गई है, जिसमें डिजिटल नगरपालिका सेवाओं की प्रदायगी के लिए सभी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग योग्य ई- गर्वनेंस समाधान शामिल है।

उपयोग पर विकसित ई-गवर्नेंस समाधान संपूर्ण शहरी इकोसिस्टम के लिए उपलब्ध हैं, इस प्रकार, ये बड़े पैमाने पर और तेजी से अनुप्रयोगों के विकास और समाधानों में सहायता करते हैं, नवाचार और सह-निर्माण की वर्चुअस साइकल बनाते हैं, और देश भर में नागरिकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, प्रशासकों, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य शहरी हितधारकों के बीच सहयोग को सशक्त करने में मदद करते हैं।

शहरी सेवाओं की डिजिटल प्रदायगी के लिए 14 सेवाएं/मॉड्यूल अपनाने और इनका कार्यान्वयन करने के लिए देश के सभी शहरों और कस्बों में इन्हें उपलब्ध करवाया गया है, जिनमें सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग और संपत्ति कर के लिए संपत्तियों का पंजीकरण शामिल है। एनयूडीएम इन सेवाओं/मॉड्यूल के कार्यान्वयन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है।

प्रायोगिक कार्यान्वयन से ली गई सीख को प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की नींव रखने और इसका निष्पादन करने के लिए समेकित किया गया है, जिसके लिए प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने के स्तर पर है।

*****